भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 662

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

पुराने वाहन बाजार के लिए सहायता

662. श्रीमती रुचि वीरा :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्क्रेप किए गए वाहनों के स्थान पर नए और अधिक दक्ष वाहनों के लिए पुराने वाहन बाजार के विकास को सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या व्यक्तियों अथवा छोटे व्यवसायियों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए कोई छूट दिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-119 (बहसूमा से बिजनौर) के अंतर्गत किसानों को मुआवजा वितरित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने व्यापार करने में आसानी और डीलरों के माध्यम से पंजीकृत वाहनों की बिक्री और खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 22.12.2022 को अधिसूचना सा.का.नि. 901 (अ) जारी की है। ये नियम पंजीकृत वाहनों के मध्यवर्तियों (इंटरमीडीयरीज)/डीलरों को पहचानने और उन्हें सशक्त बनाने में सहायक होंगे और इसके साथ ही ऐसे वाहनों की बिक्री या खरीद में धोखाधड़ी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।

(ख) नागरिकों को अपने वाहनों को स्क्रेप करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:-

- (i) सा.का.नि. अधिसूचना 714 (अ), दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान किया गया है कि, यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- (ii) सा.का.नि. अधिसूचना 720 (अ), दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) में रियायत का प्रावधान है। बशर्ते कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी।

(ग) (i) किसी विशेष परियोजना के लिए मुआवजा वितरित करने के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत जिन लाभार्थियों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा वितरित

करने के लिए सामान्य नीति/नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ज (1) के तहत, "केंद्र सरकार द्वारा भूमि पर कब्जा लेने से पहले धारा 3छ के अंतर्गत निर्धारित राशि को उस सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के आधार पर निर्धारित तरीके से सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कराई जाएगी।"

(ii) इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 18.01.2019 को सा.का.नि. 39(अ) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग (केन्द्र सरकार द्वारा राशि जमा करने का तरीका; भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराना) नियम, 2019 भी जारी किए हैं।